INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 7 | AUGUST – 2025

नल जल योजना एक वरदान या अभिशाप एवं एक प्रबंधन - शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. अजय कुमार पटेल , श्रीमती प्राची यादव
अतिथि विद्वान, इंदिरा गांधी ग्रह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश.

सारांश

प्राचीन समय में आम नागरिकों को पानी की समस्या बनी रहती थी। प्राचीन काल में आम आदमी के लिए पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना एक गंभीर समस्या थी फिर उसका उपयोग करना एक चुनौती पूर्ण कार्य माना जाता था । 21 वीं सदी में ये समस्या धीरे – धीरे कम होने लगी लोग अपने लिए पानी की समस्या के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करने लग गए जैसे कुआं खोदना, तालाब बनवाना आदि। लेकिन ये सब साधन मानव जीवन के स्वास्थ के लिए सही नहीं था। क्योंकि की जल से ही अच्छे जीवन की कल्पना की जा सकती है। प्राचीन समय में लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी न थी जिस कारणों आम जन अपने लिए बोरबेल की की व्यवस्था करने में असमर्थ थे या रुपए की कमी से नहीं कर सकते थे कुछ लोगों को छोड़कर प्राचीन समय में शहडोल जिले के लोगों की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी। यह क्षेत्र वनों से घिरा हुआ था, इसलिए लोग संग्रहण और शिकार पर भी निर्भर थे। इसके अलावा, कुछ लोग छोटे-मोटे व्यापार और दस्तकारी से भी अपनी आजीविका चलाते थे। शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां वर्तमान समय में यह के आम जन आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहे है। ऐसा नहीं है कि लोग पहले आत्म निर्भर नहीं थे जैसे कि पूर्व में विदित है कि आत्म निर्भरता के ले लिए कृषि,पशुपालन एवम् वनों पर पर निर्भरता ही आत्म निर्भरता कहलाता है। वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्र 2019 में हर घर नल जल योजना की शुरुआत की तथा 2024 तक पूरे भारत में नल जल योजना के लक्ष्य को सभी परिवारों को जल के संकट से मुक्त करने का लक्ष्य रखा।

मध्य प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल के कनेक्शन से जोड़ने के लिए 2024 तक ही लक्ष्य रखा गया।

नल-जल योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य संवर्धन और महिलाओं के श्रम में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:- आत्म निर्भरता, जलापूर्ति, उन्नति, महिला श्रम।

प्रस्तावना

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के पास एवं इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्वच्छ और आसानी से सुलभ जल उपलब्ध कराना है। भारत में जल संकट लंबे समय से एक गंभीर समस्या रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं, महिलाओं और बच्चों पर अतिरिक्त कार्यभार तथा आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के अंतर्गत "हर घर नल" योजना की शुरुआत की। इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विस्तारित किया है, इस योजना से लोगों में प्रसन्नता एवं जल के संकट से निजात दिलाना है। वर्तमान समय में नाम जल योजना मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति करना है शोधकर्ता द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में से एक जिला एवं संभाग है शहडोल जहां पर लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन से सीधे हर घर नल की व्यवस्था की गई है।

शोधकर्ता द्वारा जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के क्षेत्रांतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों का चयन कर प्राथमिक आंकड़ों के माध्यम से अपने शोध पत्र को अंतिम रूप दिया गए है, जिसमें ग्राम पंचायत खोल्हाड़, पचगांव, अंतरा, झगरहा,जोधपुर,खन्नाथ,नौगम आदि । से आंकड़ों को संकलित किया गया है, उपरोक्त वर्णित ग्राम पंचायतों में से कुछ ग्राम पंचायतों में छोड़कर अधिकांश ग्राम पंचायतों में अभी कार्य प्रगति पर है जहां पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है। ऐसा भी बोल सकते है कि केवल पाइप लाइन और नल के चैंबर ही बने पड़े है। केंद्र सरकार की इस परियोजना को मध्य प्रदेश में अभी भी पूर्ण रूप नहीं दिया गया है, जनपद पंचायत सोहागपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में फिलहाल कुछ ग्राम पंचायतों में ग्रामीण जन जीवन पाइप लाइन और चैंबर को ही देख कर खुश हो रहे है उनके लिए यह योजना एक अभिशाप जैसा लग रहा है।

उपरोक्त वर्णित ग्राम पंचायतों में यह योजना का विफल होने का कही न कही जनपद पंचायत सोहागपुर एवं संबंधित एजेंसियां है, ग्राम पंचायत ,ग्राम समिति एवं जिला प्रशासनिक व्यवस्था है। इस कारण इस योजना को ग्रामीण के कुछ क्षेत्रों में नल जल योजना एक वरदान न हो कर एक अभिशाप है, जनपद पंचायत सोहागपुर से अगर यह योजना समयबद्ध संचालित होती तो वर्तमान में यह स्थिति न होती जहां केवल पाइप लाइन और नल के बने हुए चैंबर ही दिख रहा है। पंचायती राज व्यवस्था न केवल ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित करती है,बल्कि यह शासन प्रणाली को अधिक उत्तरदायी पारदर्शी और सहभागी बनाती है।

उद्देश्य :-

- 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराना।
- स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति।
- जल स्रोतों का संरक्षण और सतत जल प्रबंधन।
- जल जनित बीमारियों में कमी लाना।
- शोधकर्ता के उद्देशों में हर घर नल जल की आपूर्ति हो रही है कि नहीं

- इस योजना को संचालित करने के लिए नियामित रूप से फंड की व्यवस्था है या नहीं ।
- हितग्राहियों से जल कर के रूप में कितना जल कर लेने का प्रावधान है
- योजना में लगे कर्मचारियों का वेतन।
- ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन मरम्मत,बिजली बिल आदि की व्यवस्था कैसे होगी।

प्रमुख मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
लाभार्थी – देश के सभी ग्रामीण परिवार
वित्तीय भागीदारी – केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खर्च वहन करती हैं।

नल जल कि प्रक्रिया –

* पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण।
* जल स्रोतों का चयन (कुएँ, बोरवेल, नदी, जलाशय)।
* शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना।
* घर-घर कनेक्शन प्रदान करना।

शोध प्रविधि :-

- शोधकर्ता द्वारा इस शोध पत्र को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।
- शोधकर्ता ने शोध कार्य से संबंधित प्रश्नावली का भी उपयोग किया गया है जिससे ग्राम पंचायतों में नल जल योजना की जलापूर्ति से संबंधित आंकड़े एकत्रित की गई है
- शोध अभिकल्पना में न्यादर्श का भी प्रयोग किया गया है ,जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 10% आंकड़े लिए गए है।
- शोध अभिकल्प में साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग किया गया है।
- यह शोध पत्र वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का उपयोग करता है।

शोध की सीमाएं :- शोधकर्ता ने अपने शोध शीर्षक " नल जल योजना एक वरदान या अभिशाप एवं एक प्रबंधन" शहडोल जिले के संदर्भ में केवल शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर क्षेत्रांतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है जो ऊपर वर्णित है।

प्रबंधन :-- नल जल योजना का प्रबंधन के लिए प्रबंध के आधारभूत सिंद्धातों का पालन करना आवश्यक है जिसमें नियोजन,संगठन,निर्देशन,नियंत्रण आदि शामिल हो

उपलब्धियां :-

- लाखों ग्रामीण घरों में नल से पानी की सुविधा उपलब्ध।

- महिलाओं और बच्चों के पानी लाने में लगने वाले समय में कमी।
- स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता में वृद्धि।

चुनौतियां :-

1. दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने में कठिनाई।
2. कुछ क्षेत्रों में जल स्रोत की कमी।
3. पाइपलाइन व शुद्धिकरण संयंत्र के रखरखाव में समस्याएं।
4. भूजल स्तर में लगातार गिरावट।

साहित्य समीक्षा :-

* शर्मा, राकेश कुमार,सहगल,महेश कुमार (2016),वैदिक काल में जल प्रबंधन, देव संस्कृति: इंटर डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल 8

* कुमार, रंजीत, डॉ.लोकनाथ (2024),जल संरक्षण के लिए स्वचालित जल स्तर नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता का अध्ययन, संचार माध्यम। खंड 36(3), ISSBN न 2321- 2608

* कुमार,विकास (2024), भारत में जल अभिशासन: सैद्धांतिक और कानूनी पृष्ठभूमि,लोक प्रशासन 16(1) पेज न 62- 74

शोध सुझाव

- वर्षा जल संचयन और जल पुनर्भरण पर जोर।
- स्थानीय स्तर पर जल समितियों का गठन।
- पाइपलाइन व जल शुद्धिकरण संयंत्रों का नियमित रखरखाव।
- जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान।
- नल जल योजना को पहले सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करना।
- जल समितियों को समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण कर भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करना।
- योजना से संबंधित कार्यों को केवल पेपर वर्क नहीं करना ।
- जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना
- पाइप लाइन व जल शुद्धिकरण संयंत्रों का नियमित रखरखाव करना।
- सोशल साइट नेटवर्क से लोकेशन ट्रेस करना।

शोध परिकल्पना :-

Ho नल जल योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान सिद्ध होती दिखाई दे रही।

H1 नल जल योजना में जलापूर्ति सही नहीं किया जाता ।

निष्कर्ष

नल-जल योजना ग्रामीण भारत के लिए जीवन-स्तर सुधारने वाली ऐतिहासिक पहल है। उचित क्रियान्वयन, रखरखाव और जल संरक्षण के प्रयासों के साथ यह योजना देश के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6 अक्टूबर 2024 तक भारत में 11.95 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल से जल के कलेक्शन प्रदान किए है । मध्य प्रदेश में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है इस योजना से लगभग 63% ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो रहा ,यह पहल न केवल जल की कमी को दूर करती है बल्कि जल लाने के बोझ को कम करके तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाकर समुदायों व विशेषकर महिलाओं को सशक्त भी बनाती है इसलिए कह सकते है कि नल जल योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, लेकिन कोई भी योजना अभिशाप तब बन जाती है जब इस योजना की देख रख ,समीक्षा नहीं की जाती है । सोहागपुर क्षेत्रांतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में यह योजना एक अभिशाप से कम नहीं है जबकि राज्य सरकार के द्वारा योजना से संबंधित शिकायतें 18001231121 पर कॉल करके या 8544429024 पर व्हाट्सएप या टेस्ट मैसेज कर सकते है। वर्तमान समय में यह योजना को सरकार महिला स्वसहायता समूह को देने का विचार कर रही है।

संदर्भ

- मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग वेबपेज – 27.06.2024
- नव भारत टाइम्स
- समाचार पत्रों के माध्यम से
- पत्रिकाएं
- **वेबसाइट**

https://www.pib.gov.in

https://pib.gov.in/press release

https://jaljeevanmission.gov.in

https://mppanchayatdarpan.gov.in

*MPPanchayat darpan Portal